चौथा संसार, इन्दौर
28 OCT 2010

सहकारी बैंक भूमि घोटाले की जांच का मुख्यमंत्री का फैसला एक साहसिक कदम

दबंगों की मिलीभगत से कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक किसानों की बरसों से हड़प रहा है जमीन

सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के अध्यक्ष दबंग व रसूकदार लोग ही रहते हैं। बैंक के पैसों का दुरुपयोग और मनमाने तरीके से लोन देना आम बात हो गई है। कृषि विकास बैंक अपने उद्देश्य से भटक गए गऐ। अब वे सिर्फ राजनीति का अड्डा बने हुए है। भाजपा शासन आने के बाद बरसों से जमे दबंगों की सफाई हुई है, लेकिन अब भी बहुत कचरा बाकी है, जिसे साफ किया जाना जरूरी है। भाजपा ने सहकारी बैंकों के निष्पक्ष चुनाव कराकर एक लोकतांत्रिक तरीके से बोर्ड का गठन किया है, लेकिन इसमें भी कुछ गलत लोग घुस गए है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान से ऐसे किसान मिलने पहुंचे जिनकी जमीन सहकारी बैंक ने बिना बताए नीलाम कर बेच दी। बैंकों ने नियमों को ताक पर रख कर लोन वसूली के लिए यह जमीन बेची। जमीन को कुछ खास लोगों ने खरीदा। पेशे से किसान मुख्यमंत्री ने जब गरीब किसानों की व्यथा सुनी तब उन्होंने तत्काल ९ बैंककर्मियों को सस्पेंड कर दिया। मुख्यमंत्री की तत्परता से उनके संकल्प का पता चलता है। अब मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर के भू-घोटाले उजागर करने के लिए केबिनेट में फैसला कर उसे पुख्ता बना दिया है। सहकारी ग्रामीण बैंकों को अब जितनी भी गलत तरीके से किसानों की जमीन बेची है, वह अब जांच के दायरे में आ जाएगी। मुख्यमंत्री के इस कदम से वे किसान लाभान्वित होंगे। जिनकी जमीन मनमानी नीलामी कर छीन ली गई। इसके साथ उन अधिकारियों का भी नकाब उतरेगा। मुख्यमंत्री शिवराज ने सहकारी कृषि व ग्रामीण विकास बैंक में हुए घोटाले की जांच का आदेश देकर एक नया पंगा लिया। अब लगता है मुख्यमंत्री की कार्यशैली बदल गई है। अब वे अपने लिए गए निर्णय पर तुरंत अमल करते है। गरीब बेसहारा किसानों का दर्द उन्हें सहा नहीं गया। मुख्यमंत्री को चाहिए कि वे जिन किसानों की जमीन अवैध तरीके से नीलाम की गई है उस जमीन को वापस किसानों को दिलवाएं। जिन दंबगों ने बैंक का पैसा डकारा है। उनकी भी जमीन नीलाम होना चाहिए।